# आकाशवाणी गोरखपुर
## प्रादेशिक समाचार

दिनांक–17 जुलाई 2024 **7:20 AM**

**पहले मुख्य समाचार।**

1. प्रदेश सरकार ने परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी पर लगाई गई रोक : मामले का हल निकालने के लिए बनाई गई विशेषज्ञ कमेटी, सभी पक्षों के साथ करेगी बैठक।
2. लखनऊ में कुकरैल रिवर फ्रंट के दायरे में आने वाले पंतनगर और इंद्रप्रस्थ नगर समेत अन्य क्षेत्रों में नहीं तोड़े जाएंगे घर : मुख्यमंत्री ने कहा– हर निवासी की सुरक्षा और शांतिपूर्ण जीवन के लिए सरकार प्रतिबद्ध।
3. केन्द्रीय विधि और न्याय राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने प्रयागराज में हमारा संविधान–हमारा सम्मान क्षेत्रीय सम्मेलन का किया शुभारंभ। कहा– प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा देता है हमारा संविधान
4. प्रदेश के 16 जिले बाढ़ की चपेट में: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे में पीड़ितों को सहायता पहुंचाने के दिये निर्देश।

**********

प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी को दो महीनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह निर्णय कल मुख्य सचिव मनोज सिंह के साथ शिक्षक संगठनों की हुई बातचीत के बाद लिया गया है। शिक्षकों की समस्याओं को सुनने और समाधान के लिए एक विशेषज्ञ समिति भी गठित करने का निर्णय हुआ है। यह समिति सभी आयामों पर अपने विचार कर सुझाव देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को शिक्षकों की समस्या का हल ढूंढ़ने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा था कि जिलाधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी शिक्षकों से संवाद स्थापित करें और उनकी समस्याएं सुनकर शासन को भेजें ताकि उनका समाधान किया जा सके। योगी सरकार ने प्रदेश के लगभग डेढ़ लाख बेसिक विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल हाजिरी की व्यवस्था लागू करने के आदेश दिए थे। आठ जुलाई से शिक्षकों को ऑनलाइन हाजिरी लगानी थी। बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक इसका विरोध कर रहे थे।

**********

लखनऊ में कुकरैल रिवर फ्रंट के दायरे में आने वाले पंतनगर, इंद्रप्रस्थ नगर समेत अन्य क्षेत्रों में घरों को नहीं तोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कल प्रभावित परिवारों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर आश्वस्त किया है कि पंतनगर हो या इंद्रप्रस्थ नगर, वहां रहने वाले लोगों की सुरक्षा और शांतिपूर्ण जीवन के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। निजी भूमि पर बने भवनों को तोड़ने की कोई योजना नहीं है। श्री योगी ने कहा कि संबंधित प्रकरण में एनजीटी के आदेशों के क्रम में नदी के फ्लड प्लेन जोन का चिन्हांकन किया गया है। फ्लड प्लेन जोन में निजी भूमि भी सम्मिलित है लेकिन निजी भूमि को खाली कराने की न तो वर्तमान में कोई आवश्यकता है और न ही कोई प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि फ्लड प्लेन जोन चिन्हांकन के दौरान भवन निर्माणों पर लगाए गए संकेतों से आमजन में भय और भ्रम फैला है, इसका कोई औचित्य नहीं था और इसके लिए जवाबदेही तय की जाएगी। संबंधित अधिकारी तत्काल क्षेत्र में विजिट करें और उनके भय और भ्रम को दूर करें।

**********

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो –सीबीआई ने नीट–यूजी पेपर लीक मामले में दो और लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें से एक आरोपी पटना से गिरफ्तार किया गया। यह झारखंड के बोकारो का निवासी है जिसपर हजारीबाग स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के केन्द्र से नीट–यूजी परीक्षा का पेपर चुराने का आरोप है। वहीं दूसरे व्यक्ति को पेपर चुराने के आरोप में हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने अब तक झारखंड के एक स्कूल से प्रधानाचार्य और सह–प्रधानाचार्य सहित चौदह लोगों की गिरफ्तारी की है।

**********

सरकार ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की छूट को अक्टूबर 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। इस संबंध में राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति–2022 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत प्रदेश में दोपहिया वाहनों पर पांच हजार रुपये और चार पहिया वाहनों पर एक लाख रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को सब्सिडी देने की व्यवस्था है, ताकि ई वाहनों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ सके। अभी तक इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर छूट सिर्फ एक साल के लिए थी, जो अक्टूबर 2023 में खत्म हो गई थी।

**********

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने कल मिर्जापुर में 19 करोड़ 61 लाख रुपये की छह विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं के अंतर्गत मां विन्ध्यवासिनी देवी तीर्थ स्थल पर सुविधाओं के विकास, चिन्दलिख गहरवार में हनुमान मंदिर के सुंदरीकरण व पर्यटन विकास का काम, नारायणपुर में बैकुंठ महादेव स्थल के पर्यटन विकास का काम समेत

अन्य काम किए जाएंगे। इस मौके पर केंद्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत विन्ध्य क्षेत्र में पर्यटन से सम्बन्धित सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।

**********

केन्द्रीय विधि और न्याय राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कल प्रयागराज में हमारा संविधान–हमारा सम्मान अभियान के दूसरे क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरूण भंसाली मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान कानूनी अधिकारों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिये हमारा संविधान–हमारा सम्मान पोर्टल लॉन्च किया गया। इस मौके पर श्री मेघवाल ने कहा कि हमारा संविधान देश के प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है, जिसके कारण ही प्रत्येक व्यक्ति अपने दायित्वों का निवर्हन करता है। यही वजह है कि आज हम विकसित भारत बनाने की ओर अग्रसर हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में असमानता को दूर करने का काम हम सबको मिलकर करना है।

कार्यक्रम के दौरान माय गव की ओर से संविधान से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया।

**********

वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सहुलियत के लिए जल्द आपातकालीन मेडिकल यूनिट स्थापित किया जाएगा। इसमें 24 घंटे चिकित्सक, नर्स और फार्मासिस्ट की तैनाती होगी। कैंट रेलवे स्टेशन के डायरेक्टर गौरव दीक्षित ने बताया कि इस इमरजेंसी रूम में एक रुपये में पर्चा बनवाकर यात्री इलाज प्राप्त कर सकेंगे। यहां पर बेसिक मेडिकल जांच की व्यवस्था भी रहेगी।

***वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन एक बहुत ही बिजी स्टेशन है तो आने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उनमें कोई इमरजेंसी मेडिकल हेल्प की कभी जरूरत है तो उनको अटेंड करने के लिए नॉर्दर्न रेलवे द्वारा एक प्राइवेट एजेंसी के साथ मिलकर एक एम ओ यू  किया गया है जिसके तहत एक इमरजेंसी मेडिकल तववउ हमारे यहाँ एब्लिश किया जा रहा है जिसमें कि एक रुपए देकर व्व्क में जो वहाँ पर तवनदक जीम बसवबा कवबजवत और चंतंउमकपबंस `जंा` रहेंगे वो कोई भी उमकपबंस समस्या होने पर चेंमदहमत उनको दिखा सकते हैं। इेंपब जो उमकपबंस जांचें होती है जैसे इसववक `नहंत है, ठच है, म्ब्ळ वगैरह वहीं पर हो जाएगा और कोई भी अगर कअंदबम जरूरत होगी तो वो किसी बाहर के कवबजवत को तमममित भी कर सकते हैं।***

**********

लगातार बारिश और बांधों से पानी छोड़े की वजह से प्रदेश में 16 जनपदों के 825 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। इसके अलावा बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर के कुछ शहरी इलाके भी बाढ़ से घिरे हैं। सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित जिलों में लखीमपुर, कुशीनगर, बलरामपुर, शाहजहांपुर, हरदोई, अयोध्या, बहराइच, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बलिया, बदायूं, देवरिया, उन्नाव, फर्रूखाबाद, बरेली और बाराबंकी जिलों के कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ की चपेट में अब तक 14 लाख से अधिक लोग आये हैं, जिनमें से पांच लाख से अधिक लोगों की फसलें, घर और सामान समेत अन्य संपत्ति नष्ट हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पीड़ितों को 24 घंटे के अंदर आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। उधर, वाराणसी में गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए अगले आदेश तक गंगा में छोटी नावों के संचालन पर रोक लगा दी गई है। गोरखपुर में बाढ़ प्रभावित 48 गांवों में 91 नाव सहायता के लिये लगाई गईं है। पीलीभीत में साढ़े सात हजार से अधिक बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी गई। हरदोई में 133 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। यहां 48 बाढ़ चौकियां और 105 शरणालय बनाये गये हैं।

शाहजहांपुर में राज्यमंत्री नरेन्द्र कश्यप ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। राशन संबंधित शिकायत मिलने पर एसडीएम सदर को तत्काल राशन बंटवाने के निर्देश दिये।

**********